आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

पहले: जे. वी. गुप्ता, जे.

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,-याचिकाकर्ता।

बनाम

कश्मीरी लाल और अन्य,-प्रतिवादी।

1989 का नागरिक संशोधन संख्या 351

19 जुलाई 1989.

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV)–एस. 110 ए–हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का XXX)–एस. 15–दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान घायल की मृत्यु–पति को पक्षकार के रूप में शामिल किया गया जिसकी दावा आवेदन के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई–मृतक की मां को पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए आवेदन–ऐसे आवेदन की वैधता।

यह माना गया कि पति की मृत्यु के बाद, जिसे उसकी मृत पत्नी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया था, जिसने मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त चोटों के लिए मुआवजे का दावा दायर किया था, पति की मृत्यु पर पत्नी की मां कर सकती थी। यह नहीं कहा जाएगा कि वह उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि है, जिसे रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। मां को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

(पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि ट्रिब्यूनल के 4 अक्टूबर 1988 के आदेश को रद्द किया जाए और संपूर्ण लागत के साथ संशोधन की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता के लिए एल.एम. सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता और रणदेव अरोड़ा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से पी. के. मलिक, वकील।

फ़ैसला

जे. वी. गुप्ता, जे.

1 जून 1986 को एक लक्ष्मी घायल हो गई थी। उसने 11 सितंबर 1986 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अपना दावा आवेदन दायर किया था। उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, 11 दिसंबर 1986 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर, उसके पति तेज

पाल ने उसे अपने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक आवेदन दिया, जिसे अनुमति दे दी गई। दुर्भाग्य से पति तेज पाल की भी मृत्यु हो गई

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कश्मीरी लाई और अन्य

(जे. वी. गुप्ता. जे.)

21 मार्च, 1988. उनकी मृत्यु पर, लक्ष्मी की माँ, ओमवती ने उन्हें अपने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन दायर किया।

बेटी लक्ष्मी. उस आवेदन का बीमा कंपनी ने विरोध किया था। ट्रिब्यूनल ने उक्त आवेदन को इस आधार पर अनुमति दी कि उसने रुपये की राशि खर्च की थी। अपनी बेटी के इलाज पर 10,000 रु और इसलिए, उसे नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा (11) के तहत परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि माना जाएगा। विद्वान न्यायाधिकरण के अनुसार ओमवती मुआवजे की हकदार होगी क्योंकि मृतक के मामले में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रतिनिधि है।

(2) याचिकाकर्ता बीमा कंपनी के वकील ने कहा कि मृतक लक्ष्मी की मां को किसी भी तरह से उसका कानूनी प्रतिनिधि नहीं ठहराया जा सकता है। लक्ष्मी की मृत्यु पर, उनके पति तेज पाल को उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाया गया था, हालांकि विद्वान वकील के अनुसार उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि यह एक चोट का मामला था और ऐसे मामलों में दावा इसके साथ ही समाप्त हो जाता है। घायल व्यक्ति की मृत्यु. अधिक से अधिक, तेज पाल के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जा सकता था, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, मृतक लक्ष्मी की माँ ओमवती, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाये जाने के लिए कोई आवेदन नहीं कर सकती थी। विद्वान वकील के अनुसार, वह न तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनकी उत्तराधिकारी थी, न ही विशेष रूप से तेज पाल की मृत्यु पर कानूनी प्रतिनिधि कहा जा सकता था। विवाद के समर्थन में, विद्वान वकील ने कलकत्ता इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम भूपिंदर सिंह (1), और >सी पर भरोसा किया। पी. कंडास्वामी बनाम मारियापा स्टार्स (2),

(3) विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क में दम नजर आया। घायल मृतिका लक्ष्मी के पति तेज पाल की मृत्यु के बाद, मृतिका लक्ष्मी की मां ओमवती को उसके उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाने के लिए ऐसा

नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में विद्वान न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत और अवैध था।

(4) नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका सफल होती है और अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। चूँकि प्रस्ताव की सुनवाई के समय आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, पार्टियों को 4 अगस्त, 1989 को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

पी.सी जी.

(1)1970 दुर्घटना दावा जर्नल 344।

(2)1974 दुर्घटना दावा जर्नल 362।

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा